



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2001/आश्विन 3, 1923

No. 261]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2001/ASAVINA 3, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2001

प्रारंभिक निष्कर्ष

विषय : नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एकीलिक यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच—प्रारंभिक निष्कर्ष

सं. 29/1/2001-डीजीएडी.— भारत सरकार वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ

अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का

आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए,

(क) **प्रक्रिया**

2. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 पंजाब फाइबर्स लि0, नवाँ शहर, पंजाब; मै0 वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि0, लुधियाना; मै0 स्पोर्टकिंग इण्डिया लि0, लुधियाना, मै0 मालवा कॉटन स्पिनिंग लि0, लुधियाना से लिखित याचिका प्राप्त हुई, जिसमें नेपाल (जिस

इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक यार्न (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

- (ii) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा पाटन से संबंधित आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया;
- (iii) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की अनुसूची 1 के उपशीर्ष संख्या 5509 के अंतर्गत और सीमाशुल्क शीर्ष संख्या 5402.39, 5402.69 के अंतर्गत वर्गीकृत नेपाल के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रिलिक यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए दिनांक 3 जुलाई, 2001 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया;
- (iv) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, वाणिज्य मंडलों और शिकायतकर्ताओं को भेजी तथा अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का उन्हें अवसर प्रदान किया;
- (v) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को और सभी ज्ञात निर्यातकों को याचिका की प्रति उपलब्ध करवाई;
- (vi) प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:
 1. मै0 रिलायंस स्पिनिंग मिल्स लि0, जिला सनसोरी, नेपाल
 2. मै0 रिलायंस स्पिनिंग मिल्स लि0, काठमांडू, नेपाल
- (vii) नई दिल्ली स्थित नेपाल के दूतावास को भी जांच शुरू करने के बारे में सूचना दी गयी थी और अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए कहे;
- (viii) नेपाल के निर्यातक ने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने की मांग की थी और प्राधिकारी ने उपरोक्त नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक द्वारा दिए गए पर्याप्त कारणों को देखते हुए निर्यातक को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान की;
- (ix) एक्रिलिक यार्न के निम्नलिखित आयातकों/उपयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी:
 1. मै0 कौर सैन ट्रेडर्स, लुधियाना
 2. मै0 गोयल एजेन्सीज, दिल्ली

उपरोक्त आयातकों ने निर्यातकों के मामले में बढ़ाए गए समय की तर्ज पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने की मांग की थी। प्राधिकारी ने उनके अनुरोध पर विचार किया और आयातकों द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों के मामले में यथा प्रदत्त एक सप्ताह का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान की।

- (x) उपयोक्ताओं/आयातकों में से मै0 कौर सैन ट्रेडर्स, लुधियाना और मै0 गोयल एजेन्सीज, दिल्ली द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया। निर्यातकों में से मै0 रिलायंस स्पिनिंग मिल्स लि0, जिला सनसोरी, नेपाल जिनका कारपोरेट/मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है, ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया;
- (xi) क्षति के बारे में याचिकाकर्ताओं से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। वह भी प्राप्त हो गयी थी;
- (xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण के लिए रखी गयी सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रख,
- (xiii) ***** यह चिह्न इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और नियमों के तहत प्राधिकारी ने इसे ऐसा ही माना है;
- (xiv) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से सूचना मांगी और उसके द्वारा दी गयी सूचना का सत्यापन किया तथा इस प्रयोजनार्थ लुधियाना, पंजाब में याचिकाकर्ताओं के परिसरों की जांच की गयी;
- (xv) प्राधिकारी ने लागत जांच भी की और सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम लागत और विनिर्माण तथा बिक्री लागत का निर्धारण किया;
- (xvi) इस जांच में 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 की अवधि शामिल है।
- (xvii) जांच शुरू करने के बारे में सूचना की प्रतियां व्यापक परिचालन हेतु फिक्की, सी आई आई, एसोचैम आदि को भी भेजी गयी थी।

ख. याचिकाकर्ताओं के विचार

3. याचिकाकर्ताओं ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं -

- (i) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन किया जा रहा एक्रिलिक यार्न संबद्ध देश से आयात किया जा रहा एक्रिलिक यार्न के समान उत्पाद है,
- (ii) नेपाल के निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं और इसलिए याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क की लेवी पर विचार करने का अनुरोध किया है;
- (iii) सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए। तथापि, वे नेपाल में विनिर्माताओं द्वारा अथवा अन्य देशों में उनके निर्यातों के लिए वसूली जा रही स्थानीय कीमतों का कोई उचित और प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार उन्होंने औद्योगिक मानदण्डों के आधार पर मूल कच्ची सामग्री के लिए उत्पादन की लागत और उपयोगिता की कीमते, विनिर्माण, प्रशासनिक और बिक्री खर्चों इत्यादि के व्यौरों के आधार पर नेपाल में सामान्य मूल्य का परिकलन किया;
- (iv) निर्यात कीमत का दावा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय कोलकाता द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए हवाई भाड़ा, बीमा, कमीशन, सामग्री के लदान के लिए समायोजनों का दावा किया गया है;
- (v) पिछले दो-तीन वर्षों में नेपाल से एक्रिलिक यार्न के आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये आयात वर्ष 1996 में 0.16 मिलियन किग्रा. से बढ़कर वर्ष 2001 में 18 मिलियन किग्रा. तक हो गए हैं। नेपाल से आयातों में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है,
- (vi) नेपाल में एक्रिलिक यार्न के विनिर्माण हेतु सृजित की जा रही क्षमता का प्राथमिक उद्देश्य केवल भारतीय बाजार को निशाना बनाना है;
- (vii) भारत में नेपाल से आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 1998-99 में 8.36% से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 27.37% हो गया है;
- (viii) नेपाल से किए जा रहे संबद्ध वस्तु के आयात पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं क्योंकि उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से काफी अधिक है। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है;
- (ix) संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन या तो स्थिर बना हुआ है अथवा उसमें गिरावट आ गयी है। जबकि एक्रिलिक यार्न की समग्र मांग में नेपाल से आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है,

- (x) घरेलू उद्योग को कीमतों में की गई कटौती के कारण क्षति उठानी पड़ी क्योंकि उद्योग अपना उत्पाद काफी घाटे में बेचने के लिए बाध्य हुआ है। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, याचिकाकर्ताओं की बिक्री प्राप्ति में वृद्धि उचित लाभप्रदता के स्तर तक नहीं हुई है। नेपाल से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत में भारी कटौती हो रही है;
- (xi) घरेलू उद्योग को कीमत ह्रासकारी/न्यूनकारी पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। नेपाल से संबद्ध वस्तु के आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमतों में कटौती, कमी की जा रही है;
- (xii) घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत से कम बिक्री कीमत पर संबद्ध वस्तु की बिक्री करने के कारण काफी हानि हुई है जिससे लगातार हानि हो रही है।

ग. निर्यातकों के विचार

4. निर्यातकों ने अपने उत्तर में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं -

- (i) भारत-नेपाल संधि के अंतर्गत भारत में वस्तुओं के सीमाशुल्क से मुक्त आयात की अनुमति है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अंतर्गत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को हैदराबाद इंडस्ट्रीज लि० बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीमाशुल्क माना गया है। इसलिए नेपाल से होने वाले निर्यातों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता;
- (ii) याचिकाकर्ताओं के पास अपेक्षित आधार नहीं है क्योंकि वे एक्रिलिक यार्न के घरेलू भारतीय विनिर्माताओं के 25% का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आधार न होने की स्थिति में जांच शुरू करना विधि सम्मत नहीं है और जांच समाप्त की जानी चाहिए,
- (iii) जांच अवधि के दौरान एक्रिलिक फाइबर की निवल उपलब्धता 1,15,299.6 मी.टन थी जिसमें फाइबर से प्राप्त यार्न 98% था, इस प्रकार भारत में एक्रिलिक यार्न का उत्पादन 112,9936 मी.टन होना चाहिए। इसकी तुलना में याचिकाकर्ताओं का उत्पादन केवल 19,883.2 मी.टन है और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का हिस्सा केवल 17.59% बनता है न कि 54% जैसा कि दावा किया गया है। याचिका में दिए गए एक्रिलिक यार्न के 36.55 मिलियन किग्रा. के उत्पादन के आंकड़े सकल रूप से कम दिखाए गए हैं। लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन इन कार्यावाइयों में एक हितबद्ध पार्टी है और इसलिए सूचना प्रामाणिक स्रोतों से एकत्रित की जाए;

(iv) याचिका में निम्नानुसार तथ्यात्मक गलतियाँ हैं -

- (क) भारत को एक्रिलिक यार्न के आयात सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 55.09 के अंतर्गत किए गए हैं तथा याचिकाकर्ताओं का यह कहना कि निर्यात अध्याय 54 और 55 के अलग-अलग उपशीर्षों के अंतर्गत किए जा रहे हैं, गलत है। यह कथन कि नेपाल के निर्यातक वस्तु के बारे में गलत घोषणा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से असत्य है। इस याचिका में एक्रिलिक यार्न के आयातों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। इस प्रकार अन्य सामग्रियों के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों से नेपाल से होने वाले एक्रिलिक यार्न के निर्यातों की मात्रा अथवा मूल्य का पता नहीं चलता है।
- (ख) यह कथन कि नेपाल में किसी अन्य प्रकार के यार्न का उत्पादन नहीं होता है, गलत है क्योंकि नेपाल में पोलिएस्टर स्पन यार्न/पोलिएस्टर टेक्सराइज्ड यार्न के अनेक ऐसे विनिर्माता हैं जो भारत को निर्यात भी करते हैं।
- (ग) यह कहना सही नहीं है कि नेपाल से होने वाले आयातों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है क्योंकि नेपाल से होने वाले आयातों पर अतिरिक्त शुल्क (सी वी डी) वसूल किया जाता है।
- (घ) नेपाल में 21 मिलियन किग्रा. की कटाई क्षमता को काफी अधिक दर्शाया गया है। यह कहना गलत है कि एक्रिलिक यार्न के लिए कोई उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं है। एक्रिलिक यार्न का प्रतिस्थापन मुख्य रूप से पोलिप्रोपिलिन यार्न तथा अन्य प्रकार के यार्न के द्वारा किया जाता है।

जब से थाइलैण्ड, कोरिया और यूएसए के एक्रिलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है तब से भारत में कच्ची सामग्री की लागत काफी अधिक हो गई है। भारतीय उद्योग सस्ती कच्ची सामग्री के स्रोत से वंचित हो गया है और परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो गया है।

(ड.) व्यावहार्य प्रतिस्थापनों की उपलब्धता के कारण एक्रिलिक यार्न की समग्र मांग में कमी आई है। यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में कमी आई है क्योंकि जांच अवधि के दौरान उत्पादन में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है।

(घ.) यह कहना गलत है कि नेपाल में उत्पादन की लागत भारत में उत्पादन की लागत से कम नहीं हो सकती है। नेपाल के निर्यातक को थाइलैण्ड से उपलब्ध सस्ता एक्रिलिक फाइबर प्राप्त हो जाता है। अतः नेपाल में विनिर्माण लागत भारत में विनिर्माण लागत से कम से कम 15 रुपए से 20 रुपए तक कम है। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया सामान्य मूल्य का निर्धारण गलत है।

(छ.) यह कहना गलत है कि नेपाल में फैक्ट्री से भारत में उपभोक्ता के गन्तय तक के भाड़े की राशि तक निर्यात कीमत में कटौती करनी चाहिए। कम किए जाने वाले भाड़े की जो राशि है वह जोगबानी में भारतीय सीमा तक की भाड़े की राशि है। किसी एजेंट को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है और वस्तु को सीधे भारत के व्यापारियों को बेचा जाता है।

(ज.) याचिका में पाटन मार्जिन का जो परिकलन किया गया है वह एकदम गलत है क्योंकि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों का परिकलन त्रुटीपूर्ण है।

(झ.) यह दावा कि याचिकाकर्ताओं को क्षति हुई है गलत है क्योंकि उत्पादन में उनके हिस्से में जांच अवधि के दौरान दोगुनी वृद्धि हुई है।

(ज) यह कहना गलत है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है क्योंकि जांच अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उद्योग की लागत में जो वृद्धि हुई है, वह शुल्क लगाने के कारण हुई है और निर्यातक को उपलब्ध परिणामी प्रतिस्पर्धी लाभ को पाटन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह उन्हें उपलब्ध विधिक लाभ है और इसलिए कथित पाटन का कोई आधार नहीं बनता है।

(ट) उचित बिक्री कीमत के परिकलन में याचिकाकर्ताओं ने 10% का लाभ मार्जिन दर्शाया है जो घरेलू स्तर की तुलना में बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत फाइबर पर शुल्क के कारण अधिक है और याचिकाकर्ताओं ने अक्षमतापूर्ण कार्य किया है और अत्यधिक वित्तीय लागत के बोझ से दबे पड़े हैं। यह कहना गलत है कि संबद्ध वस्तु का पहुँच मूल्य याचिकाकर्ताओं की उत्पादन लागत से कम है।

(ठ) नेपाल से हुए निर्यातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध का पूर्णतः अभाव है। क्षति, यदि कोई हो, समग्र मांग में आई कमी और एक्रिलिक फाइबर पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण हुई है।

(व) इस मामले में पाटन का पूर्ण अभाव है। निर्यातकों के अनुसार, अपने एकमात्र बाजार अर्थात् भारत को किए गए निर्यातों में घाटा उठाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं हैं। उन्होंने नेपाल में एक्रिलिक ग्रे यार्न की कोई बिक्री नहीं की है। अतः ग्रे यार्न की घरेलू कीमतें उपलब्ध नहीं हैं।

(vi) याचिकाकर्ता को हुई क्षति का पूर्ण अभाव है जैसा कि यह बात स्पष्ट है कि जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस मामले में कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक उत्पादन लागत दर्शायी है जो फाइबर की उच्च प्रति इकाई कीमत, अधिक ब्याज लागत, प्रति वर्ष मानव घण्टों की कम संख्या और निम्न उत्पादकता के कारण बढ़ी हुई है। क्षति, यदि कोई हो, नेपाल से निर्यातों के कारण नहीं हुई है।

(vii) निर्यातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह पाटित आयातों जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो, से इतर अन्य ज्ञात कारकों की जांच करें।

(viii) भारतीय उद्योग को क्षति होने का मुख्य कारण एक्रिलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव है। इन शुल्कों ने भारतीय विनिर्माताओं को सस्ते एक्रिलिक फाइबर की पहुँच से वंचित कर दिया है। इससे भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हुई है।

(घ) प्राधिकारी द्वारा जांच एवं निष्कर्ष

5. इन निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और इनके द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है और जहाँ उचित पाया गया वहाँ इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकारी ने पाया है कि निर्यातक न प्रश्नावली के बारे में चुनिंदा उत्तर दिया है। प्रारंभिक उत्तर में निर्यातक ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्रियों के बारे में उत्तर न देना उचित समझा। इसी प्रकार, परिशिष्ट-3 में यथापेक्षित चालू वर्ष और पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए घरेलू बाजार में हुई बिक्रियों के बारे में सूचना नहीं दी गई थी। पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए निर्यात बिक्रियों के बारे में उचित तुलना के लिए अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए सूचना नहीं दी गई थी बल्कि 17 जुलाई से 16 जुलाई तक की अवधि के आंकड़े दिए गए थे। घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री ढांचा कीमत (परिशिष्ट-5), फैक्ट्री लागत और घरेलू बिक्रियों के लाभ (परिशिष्ट-9) के बारे में सूचना नहीं दी गयी थी। घरेलू बिक्रियों के बारे में प्रदत्त सूचना स्पष्ट करने के बारे में पूछने पर निर्यातक ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्री सौदों के बारे में सूचना दी थी। अतः निर्यातक ने चुनिंदा सूचना दी थी और पूरा उत्तर नहीं दिया था। जहाँ उचित पाया गया वहाँ उत्तर में पायी गई कमियों पर इन निष्कर्षों में कार्रवाई की गई है।

6. नए निर्यातकों अथवा कीमत संबंधी वचन-पत्र देने के इच्छुक निर्यातकों के मामलों पर अनुरोध करने पर उपरोक्त नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा ।

ड. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7 विचाराधीन उत्पाद एक्रिलिक यार्न है । एक्रिलिक यार्न एक्रिलिक फाइबर से बना होता है और मुख्यतः 3-4 काउंट में बुना हुआ होता है । इसका निर्माण या तो 100% एक्रिलिक फाइबर अथवा 10% पालिस्टर अथवा विस्कोस के मिश्रण के साथ 90% एक्रिलिक फाइबर के संयोजन से अथवा 15% पालिस्टर अथवा विस्कोस के मिश्रण के साथ 85% एक्रिलिक फाइबर से किया जाता है । एक्रिलिक यार्न का इस्तेमाल कताई-बुनाई, हौजरी, शॉल इत्यादि के उत्पादन में किया जाता है । एक्रिलिक यार्न का आयात सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण मुख्य शीर्ष 5402 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 5402.39 और 5402.69 तथा मुख्या शीर्ष 5509 के उप-शीर्षों के अंतर्गत होता है । तथापि ये सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी प्रकार से जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं ।

8 याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु नेपाल मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान है । निर्यातकों ने अपने प्रारंभिक उत्तर में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं उठाई और चुनिंदा सूचना पदान की थी । तथापि, जब उनसे घरेलू बिक्रियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने यह बात उठाई कि ग्रे और डाइड एक्रिलिक यार्न पर अलग-अलग उत्पादों के रूप में विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अदला-बदली नहीं की जा सकती है । ऐसा करते समय निर्यातकों ने प्रश्नावली की परिशिष्ट-1 के अंतर्गत यथापेक्षित एक्रिलिक डाइड यार्न की घरेलू बिक्रियों का ब्यौरा दिया था । प्राधिकारी ने समान वस्तु के बारे में निर्यातकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जांच की है । वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद दिनांक 3.7.2001 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के पैरा-2 में यथोल्लिखित एक्रिलिक यार्न है । एक्रिलिक डाइड यार्न को वर्तमान जांच के दायरे से अलग नहीं रखा गया था । जांच

अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात के बारे में जो सूचना है इसमें एक्रिलिक डाइड यार्न के निर्यातों की सूचना भी शामिल है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि एक्रिलिक ग्रे यार्न और एक्रिलिक डाइड यार्न तकनीकी रूप से एक ही उत्पाद हैं। सिवाय इस बात के कि ग्रे यार्न को जब रंग दिया जाता है तो वह डाइड यार्न बन जाता है। ये दोनों पारस्परिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी एक्रिलिक डाइड यार्न को वर्तमान जांच से अलग करने की निर्यातक की मंशा से सहमत नहीं थे और इसलिए जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु को शामिल उत्पाद अर्थात् उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित एक्रिलिक यार्न के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

(च) घरेलू उद्योग

9. भारत में संबद्ध वस्तु के अनेक उत्पादक हैं। तथापि, यह याचिका मैसर्स पंजाब फाइबर्स लि०, नोवा शहर, पंजाब, मैसर्स वर्द्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लि, लुधियाना, मैसर्स स्पोर्टकिंग इंडिया लि, लुधियाना, मैसर्स मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लि, लुधियाना द्वारा दायर की गई है। याचिका के अनुसार, अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 (जांच अवधि) के दौरान एक्रिलिक यार्न का अनुमानित उत्पादन 36.65 मिलियन किग्रा. हुआ था और इस अवधि के दौरान चारों याचिकाकर्ताओं का उत्पादन 19.884 मिलियन किग्रा. रहा था जो उत्पादन का 54.4% बनता है। तथापि, एक्रिलिक यार्न के उत्पादन संबंधी आंकड़ों का सत्यापन वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई से किया गया था जिन्होंने सूचित किया है कि जांच अवधि के दौरान एक्रिलिक स्पिन यार्न का कुल उत्पादन 64.94 मिलियन किग्रा. हुआ था और चारों याचिकाकर्ताओं का हिस्सा 22.59 मिलियन किग्रा. था जो 34.79% बनता है। निर्यातक ने याचिकाकर्त के आधार के बारे में सवाल उठाया है। तथापि, उन्होंने एक्रिलिक यार्न के उत्पादन संबंधी आंकड़े एक्रिलिक फाइबर से प्राप्त किए हैं। किसी अन्य प्रयोग के अतिरिक्त, विभिन्न यार्नों के मिश्रण के निर्माण में एक्रिलिक फाइबर के प्रयोग की संभावना है। भारत से भी एक्रिलिक फाइबर का कुछ निर्यात हुआ है। चूंकि निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान एक्रिलिक यार्न के उत्पादन के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं किए हैं इसलिए प्राधिकारी वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई से प्राप्त सूचना पर विश्वास करना उचित मानते हैं और उन याचिकाकर्ताओं का उपरोक्त नियम-5 के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि

माना जाता है जो समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25% से अधिक उत्पादन करते हैं। जांच की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने भी नेपाल से एक्रिलिक यार्न के पाटन के बारे में पाटनरोधी जांच करने संबंधी याचिका का समर्थन किया है :-

घरेलू उत्पादक का नाम	2000-01 में उत्पादन (मि.टन)
मैसर्स वर्धमान पोलिटेक्स, लुधियाना	2333
मैसर्स गर्ग एक्रिलिक्स लि, लुधियाना	983.5
मैसर्स आदिनाथ टेक्सटाइल्स लि, लुधियाना	895
मैसर्स महावीर स्पिनिंग मिल्स, लि. लुधियाना	3240
मैसर्स आरिसुदाना इंडस्ट्रीज लि., लुधियाना	3820
मैसर्स दीपक स्पिनर्स लि0, चण्डीगढ़	2296
मैसर्स सुप्रीम बूलन मिल्स लि, लुधियाना	4997

छ. पाटन और सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में किए गए दावों की जाँच

10. धारा(9) क(1) (ग) के अन्तर्गत किसी वस्तु के बारे में सामान्य मूल्य का अर्थ है :

- (i) व्यापार के सामान्य रूप में मिलती-जुलती वस्तुओं का तुलनात्मक मूल्य जबकि यह निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए हो, जिसका निर्धारण उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाए; या
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य रूप में मिलती-जुलती वस्तुओं की कोई बिक्री न हो, या निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती हो, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा -
- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर मिलती-जुलती वस्तुओं का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य, जिसका निर्धारण उप-धारा (6) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा या

(ख) प्रशासनिक लागतों, बिक्री-लागतों और सामान्य लागतों एवं लाभो के लिए उचित राशि जोड़ते हुए उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जिसका निर्धारण उप-धारा (6) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा

11. प्राधिकारी ने धारा 9क(1) (ग) के अनुसार मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ज्ञात निर्यातकों से प्रश्नावली भेजी थी । तथापि उत्तर केवल मै0 रिलायंस स्पिनिंग मिल्स लि., जिला सुनसोरी, नेपाल से ही प्राप्त हुआ था जिनका निगमित/मुख्यालय काठमांडु, नेपाल में स्थित है । निर्यातकों के अनुसार उन्होंने नेपाल में एक्रीलिक ग्रे यार्न की कोई बिक्री नहीं की है । अतः ग्रे यार्न की घरेलू कीमते उपलब्ध नहीं हैं । जहां तक डाइड एक्रीलिक यार्न का संबंध है उन्होंने इसकी 1/40 के काउंट में बहुत ही कम मात्रा में निर्यात किया है । तथापि इस काउंट के एक्रीलिक यार्न की बिक्री नेपाल के घरेलू बाजार में नहीं की गई है । अतः निर्यातक के अनुसार नेपाल में घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । यद्यपि निर्यातक ने घरेलू बिक्रियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की थी तथापि जो सूचना उसने प्रस्तुत की थी उसके जांच में शामिल उत्पाद अर्थात् एक्रीलिक यार्न की घरेलू बिक्रियां प्रदर्शित होती थी । निर्यातक से इस असंगतता के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था । निर्यातक ने यह कहते हुए उत्तर दिया था कि ग्रे और डाइड एक्रीलिक यार्न अलग-अलग उत्पाद के रूप में विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अदल-बदल नहीं सकते हैं । स्पष्टीकरण देते समय निर्यातक ने एक्रीलिक डाइड यार्न की घरेलू बिक्रियों के बारे में सूचना प्रस्तुत की थी । घरेलू बिक्रियों के लिए बिक्री कीमत ढांचे के बारे में निर्धारित प्रपत्र में पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है । परिशिष्ट 9 के अनुसार फैक्ट्री लागत और घरेलू बिक्री से प्राप्त लाभ के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है । निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक्रीलिक डाइड यार्न की घरेलू बिक्रियों की मात्रा 100 मी. टन है । यह मात्रा जांच अवधि के दौरान निर्यातक द्वारा शामिल उत्पाद को दिए गए निर्यातों का 2.3% बनती है । धारा 9क (1) (ग) (11) के अनुसार जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं की जाती है अथवा जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशिष्ट बाजार स्थिति या बिक्रियों की कम मात्रा की वजह से ऐसी बिक्रियों की उचित तुलना नहीं की जा सकती हो तो सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा -

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन में लागत:

12. यहां पर पाटनरोधी डब्ल्यू टी ओ करार प्रासंगिक है। " घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा' स्पष्टीकरण पाद टिप्पणी के रूप में दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि " निर्यातक देश के घरेलू बाजार में खपत के लिए नियत समान उत्पाद की बिक्री को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सामान्यतः पर्याप्त माना जाएगा यदि ऐसी बिक्री आयातक सदस्य के विचाराधीन उत्पाद की बिक्रियों का 5 % अथवा उससे अधिक बनती हो, किन्तु जहां साक्ष्य यह दर्शाते हों कि ऐसे कम अनुपात पर की गई घरेलू बिक्रियां समुचित तुलना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है वहां कम अनुपात स्वीकार्य होना चाहिए। इस मामले में एक्रिलिक डायड यार्न की घरेलू बिक्री निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा 2.3 % बनती है। अतः ये घरेलू बिक्रियां समुचित तुलना करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती हैं। प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार निर्यातक द्वारा किसी अन्य देश को कोई निर्यात नहीं किया गया है। अतः किसी तीसरे देश को निर्यात किए जाने की स्थिति में उत्पाद की तुलनात्मक प्रतिनिधि कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए धारा 9क (1)(ग) (ii)(क) भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

13. इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए धारा 9क(1)(ग)(ii)(ख) लागू होती है अर्थात् सामान्य मूल्य का निर्धारण उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर किया जाना है। सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 10 तथा अनुबंध-1 के सिद्धांत 1 के अनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत के घटक का निर्धारण सामान्यतः जांचाधीन निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्यतः स्वीकार्य

लेखा सिद्धांतों के अनुसार रखे गए हों, और ऐसे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार रखे गए हों, और ऐसे रिकार्ड विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बेक्री से संबद्ध लागत को समुचित रूप से दर्शाते हों। इस मामले में जांच की अवधि 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की है। निर्यातक ने विभिन्न कारणों से उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी और इन कारणों में से एक कारण यह था कि नेपाल में वित्तीय वर्ष हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 17 जुलाई से शुरू होता है, जो कि जांच की अवधि से भिन्न है और इसलिए उन्हें जांच की अवधि को ध्यान में रखते हुए सूचना तैयार करनी थी। प्राधिकारी ने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय को एक सप्ताह तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी। इस समय वृद्धि के बाद भी निर्यातक ने जांच की अवधि के लिए पूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय सूचना अपूर्ण है क्योंकि तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे 16 जुलाई 2000 से 13 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए हैं जो जांच अवधि हेतु विचाराधीन उत्पाद की लागत निर्धारण संबंधी सूचना के उचित सत्यापन की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है। कारखानागत लागत तथा घरेलू बिक्रियों के लाभ की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की गई है। घरेलू बिक्री के लिए बिक्री कीमत ढांचा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी प्रस्तुत की गई लागत निर्धारण संबंधी पर ध्यान नहीं देते हैं। निर्यातक द्वारा लागत निर्धारण के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कच्ची सामग्री की लागत, ब्याज एवं वित्तीय खर्चों के लेखे, प्रति फ्रेम लागत का अक्वंटन, रंजक एवं रसायन लागत इत्यादि के संबंध में किए गए दावों का पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर सत्यापन किया जाता है।

14. अतः प्रारंभिक निर्धारण के लिए प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। ऐसा करते समय प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा कच्ची सामग्री अर्थात् एक्रिलिक फाइबर की लागत के संबंध में प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया है। निर्यातक ने कच्ची सामग्री एक्रिलिक फाइबर की सीआईएफ कलकत्ता कीमत के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तथापि, प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री के निर्यातक के कारखाने में पहुंचने तक के भाड़े और सीमा निकासी प्रभारों के रूप में *** रु0 जोड़ दिए हैं। सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्पादन, बिक्री लागत सामान्य एवं प्रशसनिक खर्चों का निर्धारण किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अंतिम

निर्धारण होने तक विचाराधीन उत्पाद के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य ***
रु0/किग्रा0 *** अमरीकी डालर/किग्रा0 है ।

निर्यात कीमत

15. मै0 रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स लि0, जिला सुन्सोरी नेपाल ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए अपने निर्यातों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । प्रस्तुत किए गए निर्यात संबंधी विवरण पत्र में एक्रिलिक डाइड यार्न के निर्यातों के पांच परेषण हैं और बाकी परेषण एक्रिलिक 100 % ग्रे यार्न के निर्यात से संबंधित हैं । रंजक लागत के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यातों के एफओबी मूल्य में आवश्यक समायोजन किए गए हैं । इन समायोजनों के पश्चात भारत को एक्रिलिक यार्न की भारत औसत एफ ओ बी निर्यात कीमत *** रु0 *** अमरीकी डालर प्रति किग्रा0 बनती है । निर्यातक ने स्वदेशी भाड़े (जोगबनी तक), बीमा, उद्गम संबंधी प्रमाण पत्र, निर्यात शुल्क, हैंडलिंग तथा फारवर्डिंग के कारण निर्यात कीमत के निर्धारणीय मूल्य में से *** रु0, *** अमरीकी डालर का समायोजन दर्शाया है । निर्यातक ने दावा किया है कि नेपाल सीमा से लुधियाना में गन्तव्य स्थान तक का भाड़ा आयातकों द्वारा वहन किया जाता है और निर्यात बीजक में डिलीवरी की कोई शर्त अर्थात् एफ ओ बी अथवा सी आईएफ नहीं दर्शाई जाती है । प्रस्तुत किए गए प्रवेश बिल के अनुसार भाड़े (कारखाने से नेपाल सीमा तक), बीमा, उद्गम संबंधी प्रमाणपत्र के प्रभार, लोडिंग प्रभार तथा नेपाली सीमाशुल्क प्रभारों के कारण राशि को जोड़ने के पश्चात आकलनीय मूल्य का निर्धारण किया जाता है । चूंकि ये प्रभार नेपाल सीमा पर वस्तुओं के पहुंचने तक किए गए हैं और निर्यात बीजक के अनुसार केवल आयातक इस राशि का भुगतान करता है, इसलिए बीजक मूल्य में से इनके संबंध में समायोजन करना उचित माना गया है । इसलिए भारत औसत निर्यात कीमत में से इस संबंध में *** रु0 *** अमरीकी डालर/किग्रा0 का समायोजन किया गया है । इन समायोजनों के पश्चात जांच अवधि के लिए निवल निर्यात कीमत *** रु0 *** अमरीकी डालर प्रति किग्रा0 निकाली गई है ।

पाटन मार्जिन

16. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और पाटनरोधी नियमों में यथा उल्लिखित सामान्य मूल्य नियोजित कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांत नियमावली के अनुबंध-

1 में विस्तार से दिए गए हैं। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने गणना और तुलना व्यापार के समान स्तर पर की है। कारखानाद्वारा स्तर पर उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की तुलना भारत की गई है। ऐसा करते समय रंजक लागत के लिए पर्याप्त छूट दी गयी है।

17. सामान्य मूल्य *** रु0 *** अमरीकी डालर प्रति किग्रा० निकाला गया है जो परिकलित उत्पादन लागत पर आधारित है। कारखानाद्वारा स्तर पर निवल निर्यात कीमत उपरोक्तानुसार निकाली गई है और समायोजनों के पश्चात यह *** रु0 *** अमरीकी डालर प्रति किग्रा० बनती है। मै० रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स लि०, नेपाल द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत का 45.9 % बैठता है।

ज. क्षति

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

क्षति का निर्धारण:

- (1) निर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा कि भारत में होने वाले ऐसे आयातों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में बाधा आती है ;
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे और घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा और पाटित आयातों की मात्रा, और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों के अनुबंध II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करेंगे।

पाटनरोधी नियमों के अनुबंध- II में क्षति के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि:

i. क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी ।

ii. पाटित आयातों के मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है । नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत उस वृद्धि को रोकना है जो कि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती ।

19. प्राधिकारी ने जांच की अवधि तथा पिछले दो वर्षों अर्थात् 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आयातों की मात्रा से संबंधित सूचना की जांच की है । प्राधिकारी ने जांच की अवधि तथा पिछले दो वर्षों अर्थात् 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आयातों की मात्रा से संबंधित सूचना की जांच की है । प्राधिकारी ने यह पाया है कि इन वर्षों से संबंधित आयातों की मात्रा में काफी भिन्नता है जैसा कि विभिन्न स्रोतों जैसे कि वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस), याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा नेपाल में भारतीय दूतावास में दर्शाया गया है । जांच शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में डीजीसीआईएस ने आईटीसी वर्गीकरण 5402.39/69, 5590.61/62/69 के अंतर्गत नेपाल से एक्रिलिक यार्न के आयातों को दर्शाते हुए 1999-2000 में 3436 मी० टन तथा (अप्रैल 2000-फरवरी 2001) के दौरान 1165 मी० टन के आंकड़े भेजे । भिन्न-भिन्न स्रोतों की आयात संबंधी मात्राओं में व्यापक भिन्नता को देखते हुए प्राधिकारी आयातों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की तुलना निर्यातक तथा आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर करना उचित मानते हैं । निर्यातक द्वारा प्रस्तुत पिछले दो वर्षों के निर्यातों से संबंधित सूचना उपयोगी नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि निर्यातकों ने यह सूचना नेपाली वित्तीय वर्ष अर्थात् 17 जुलाई से 15 जुलाई तक के संदर्भ में दी थी जबकि, जांच की अवधि 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक की थी । इससे उचित तुलना नहीं हो सकती है । दोनों आयातकों

द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर आयात 1998-99 में 4790 मी० टन से बढ़कर 1999-2000 में 7481 मी० टन हो गए जिनमें 56 % की वृद्धि दर्ज हुई और 1999-2000 में 7481 मी० टन से बढ़कर 2000-01 में 9572 मी० टन हो गए जिनमें 27 % की वृद्धि दर्ज हुई। प्राधिकारी यह पाते हैं कि नेपाल से आयातों की मात्रा में पिछले तीन वर्षों के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान शामिल उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। भारत में उत्पाद की मांग के संबंध में आयातों में 1998-99 में 6.53 % से 2000-2001 में 12.8 % तक की अत्यधिक वृद्धि भी हुई है।

20. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अन्यथा काफी हद तक कमी लाना है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि नेपाल और विशेषकर उस निर्यातक जिसने प्रश्नावली का उत्तर दिया है, से हुए पाटित आयात काफी बढ़ गए हैं। जांच की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में आयातों में 27 % की वृद्धि हुई है। उत्पाद की भारतीय मांग में उनका हिस्सा भी 1998-99 में 6.53 % से बढ़कर 2000-01 में 12.8 % हो गया है जो कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

अत्यधिक कीमत कटौती

21. आयातों की कीमत कटौती से घरेलू उद्योग की कीमत पर काफी न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग किसी उचित बिक्री कीमत को प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है। जांच की अवधि के दौरान शामिल उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की औसत निवल बिक्री प्राप्ति *** रुपए/किग्रा० रही है जबकि आयातित उत्पाद का औसत पटुंग मूल्य *** रु०/किग्रा० रहा है। यह स्पष्ट तौर पर कीमत कटौती दर्शाता है।

22. कीमत कटौती संबंधी साक्ष्य यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। उद्योग संबद्ध वस्तु के अपने उत्पादन पर उचित बिक्री कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा है जिससे वह अपनी लागत वसूल कर सकता और समुचित लाभ कमा सकता है।

क्षति का खतरा

23. उपरोक्त नियम 11, अनुबंध II के अनुसार जब क्षति के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान का निर्धारण करते समय पाटित आयातों की मात्रा, समान उत्पाद की घरेलू बाजार कीमतों पर इनके प्रभाव और उसके फलस्वरूप ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, क्षति के खतरे के संबंध में उपरोक्त नियमों के II के पैरा (vii) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"(vii) वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि केवल आरोप, अनुमान या परोक्ष संभावना पर। परिस्थितियों में बदलाव, जो ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें पाटन से क्षति होती हो, स्पष्ट तौर पर पूर्वानुमानित और आसन्नवर्ती होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्न कारकों पर विचार करेगा ;

(क) भारत में पाटित आयातों की पर्याप्त वृद्धि दर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाती हो ;

(ख) निर्यातक की पर्याप्त गुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता या क्षमता में आसन्नवर्ती पर्याप्त वृद्धि, जिससे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार को अत्यधिक संबंधित पाटित निर्यातों की संभावना का पता चलता हो ;

(ग) क्या आयात उन कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इससे आगे और आयातों की मांग में वृद्धि की संभावना होगी ; और

(घ) वस्तुओं की स्टॉक की जांच की जा रही है।"

24. बड़ी मात्रा में पाटित आयातों के जारी रहने से कीमतों में मंदी आई है और घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को उस स्तर तक बढ़ाने में अक्षम रहा है जिस स्तर पर वह अपनी लागत प्राप्त कर सके और उचित लाभ अर्जित कर सके। जांच अवधि और पिछले वर्ष के दौरान पाटित आयातों की मात्रा काफी अधिक रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि आयात बड़ी मात्रा में पाटित कीमतों पर जारी रह सकते हैं जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा हो सकता है। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा बना हुआ है।

अ. कारणात्मक संबंध

25. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-11 के सिद्धांत (iv) में यह उल्लेख है "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें शामिल है, बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित कमी, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी स्टॉक, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजीगत निवेश का बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव।

निर्यातक के विचार

26. निर्यातक का यह तर्क है कि फाइबर की उच्च यूनिट कीमत, उच्च ब्याज लागत, प्रति वर्ष मानव घटों की कम संख्या और कम उत्पादकता की वजह से याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा-इंगित उत्पादन लागत काफी अधिक है। क्षति, यदि कोई हो, तो वह नेपाल से हुए निर्यातों की वजह से नहीं हुई है। इसके आलवा, याचिका में दी गई उचित बिक्री कीमत की गणना गलत है और इसमें अनेक अदृश्य लागतें शामिल हैं। उचित बिक्री कीमत का निर्धारण फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव और याचिकाकर्ताओं की कम कार्य-क्षमता को दूर करने के पश्चात किया जाना चाहिए। निर्यातकों के अनुसार, कोई पाटन या क्षति नहीं हुई है और निर्यात तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति,

यदि कोई हो, के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मुख्य कारण एक्रीलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव है। इन शुल्को से भारतीय विनिर्माता सस्ता एक्रीलिक फाइबर की प्राप्ति से बेहद वंचित रहा है।

याचिकाकर्ताओं के विचार

27. याचिकाकर्ताओं ने यह बताया है कि नेपाल में उत्पादन-लागत भारत में उत्पादन लागत से भिन्न नहीं हो सकती बशर्ते कि भारत में संदेय सीमाशुल्क के कारण कच्ची सामग्री की लागत में अन्तर न हो। निर्यातकों की अपनी स्वयं की स्वीकारोचित के अनुसार नेपाल के उत्पादकों को कम से कम 15-20/-रुपए किग्रा. का लागत लाभ मिलता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 17.50 रुपए (निर्यातक द्वारा किए गए दावे का औसत) का लाभ देकर भी नेपाल के उत्पादकों द्वारा निर्यात 17.50 रुपए/किग्रा. के इस अंतर से भी अधिक अन्तर पर किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि नेपाल के निर्यातक अपनी उत्पादन लागत प्राप्त नहीं कर पाए और निर्यातकों द्वारा दर्ज की गई मुख्य सूचना को छिपाया गया है।

प्राधिकारी की जांच एवं निष्कर्ष

28. भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने आगे और ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जैसे उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति इत्यादि। घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले उपरोक्त सभी आर्थिक मानदण्डों की जांच की गई है। चारों याचिकाकर्ताओं का उत्पादन 1998-99 में 2039 मीट्रिक टन, 1999-2000 में 22300 मीट्रिक टन और जांच अवधि (अप्रैल-मार्च, 2001) के दौरान 22594 मीट्रिक टन रहा है। कुल उत्पादन में मामूली सी वृद्धि हुई है। तथापि, आयातों में समग्र रूप से हुई वृद्धि के कारण, इनका बाजार हिस्सा 1999-2000 में 32.7% से घटकर जांच अवधि में 30% रह गया, जबकि संबद्ध देश से आयात का हिस्सा 1998-99 में 6.5% से बढ़कर जांच अवधि में 12.8% हो गया। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में 27% तक की

समग्र वृद्धि हुई थी। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत ... रूपए/किग्रा. से बढ़कर ...रु0/किग्रा. हो गई है। 1999-2000 के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति ...रु/किग्रा और जांच अवधि के दौरान ...रु./किग्रा. रही है। निवल बिक्री प्राप्ति को उत्पादन लागत से कम पाया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्पादन और शामिल उत्पाद की बिक्री की वजह से हानि हुई है। पर्याप्त कीमत कटौती होने के साक्ष्य मिले हैं क्योंकि शामिल उत्पाद की पहुँच कीमत निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। कीमतों में मंदी की वजह से भी घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है क्योंकि आयातित उत्पाद की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में मंदी रही है और घरेलू उद्योग उचित लाभ अर्जित करने के लिए अपनी कीमतों को उस स्तर तक बढ़ाने में नाकाम रहा है।

29. प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन संबद्ध देश से आयातों में हुई पर्याप्त वृद्धि के कारण स्थिर रहा है। चूंकि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत की वसूली करने और उचित लाभ कमाने के लिए उचित बिक्री कीमत की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं था इसलिए घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन बढ़ाने से रोका गया था। घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में मामूली सी हुई वृद्धि यह नहीं दर्शाती है कि क्षति की स्थिति पैदा नहीं हुई है, जबकि उद्योग को अपनी इष्टतम क्षमता से कम पर उत्पादन करने के लिए बाध्य किया गया है। उद्योग की औसत निवल बिक्री प्राप्ति उत्पाद की उत्पादन लागत से कम है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। पाटित आयातों के कारण उद्योग को उस स्तर तक अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने से रोका गया है जिस स्तर पर उत्पादन लागत की वसूली की जा सके और निवेश पर उचित लाभ मिल सके। उचित बिक्री कीमत की वसूली न होने के कारण हुई क्षति काफी गंभीर रही है जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है।

30. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयात के कारण हुई थी, प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि ही वह वजह है जिससे घरेलू उद्योग उस स्तर पर अपनी क्षति रहित कीमत को प्राप्त करने के लिए नाकाफी स्तर तक अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य हुआ

है। इसलिए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध है। इसलिए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध है।

ज क्षति पहुँचाने वाले कारकों की जांच

31. निर्यातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मुख्य कारण एक्रीलिक फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव है। इन शुल्कों से भारतीय विनिर्माता सस्ता एक्रीलिक फाइबर प्राप्त करने से वस्तुतः वंचित रहा है। निर्यातक ने एक्रीलिक यार्न की समूची मांग में आई कमी को भी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना है।

32. प्राधिकारी ने इन तर्कों की जांच की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि नेपाल में एक्रीलिक फाइबर के आयात पर पाटनरोधी-शुल्क नहीं लगता है जबकि भारत में विनिर्दिष्ट देशों और निर्यातकों से किए गए एक्रीलिक फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। ऐसा करते समय भी प्राधिकारी ने संबद्ध देश से हुए संबद्ध उत्पाद के आयात में पाटन को पाया है। जहां तक निर्यातकों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति एक्रीलिक यार्न की समूची मांग में आई कमी के कारण हुई है, प्राधिकारी अंतिम निर्धारण होने तक यह पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान भारत में एक्रीलिक यार्न की मांग में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी आई है जबकि निर्यातक का हिस्सा 1998-99 में 6.5% से बढ़कर जांच अवधि में 12.82% हो गया है।

(ट) भारत - नेपाल संधि

33. निर्यातक के अनुसार, नेपाल से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी-शुल्क नहीं लगाया जा सकता क्योंकि भारत और नेपाल ने व्यापार तथा पारगमन के मामलों में सहयोग संबंधी करार किया

है। उक्त संधि के खण्ड-5 के अनुसार भारत सरकार को नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में सीमाशुल्क से मुक्त पहुँच की सुविधा प्रदान करनी होगी। निर्यातक के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9(क) के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क एक तरह का शुल्क है और इसलिए इसे भारत-नेपाल संधि के अंतर्गत नहीं लगाया जा सकता है। 1996 की भारत-नेपाल संधि संबंधी दस्तावेज के अनुसार अनुच्छेद- IV में यह उल्लिखित है कि "भारत सरकार, नेपाल में विनिर्मित सभी वस्तुओं के लिए सीमाशुल्कों और मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त भारतीय बाजार में पहुँच की सुविधा प्रदान करेगी"। उक्त अनुच्छेद- IV के साथ संलग्न उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र से यह मुद्दा स्पष्ट हो जाता है क्योंकि उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र के शीर्षक में "नेपाल की महामहिम सरकार और भारत सरकार के बीच व्यापार संधि के अंतर्गत मूलभूत और आनुषंगिक शुल्कों से मुक्त निर्यातों के लिए" उल्लिखित है। इसलिए उक्त संधि में मूलभूत और आनुषंगिक शुल्कों की लेवी से छूट का उल्लेख है न कि सभी प्रकार के सीमाशुल्कों से निर्यातक की खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार नेपाल से होने वाले आयातों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत अतिरिक्त सीमाशुल्क (सामान्यतः सीवीडी के रूप में ज्ञात) वसूल किया जाता है। निर्यातक ने हैदराबाद इंडस्ट्रीज लि० बनाम भारत सरकार के मामले का उल्लेख किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिनियमों या नियमों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न प्रकार के सीमाशुल्कों के संबंध में अपना मत व्यक्त किया है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के शुल्कों में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क को भी शामिल किया गया है। यदि निर्यातक का तर्क यह है कि नेपाल से होने वाले आयातों पर कोई सीमाशुल्क नहीं लगाया जाता है तो उनकी खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार नेपाल से होने वाले आयातों पर सीमाशुल्क अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाया जाता है। इसलिए, यह मानते हुए भी कि पाटनरोधी शुल्क एक प्रकार का सीमाशुल्क है, वह नेपाल से होने वाले आयातों पर लगाया जा सकता है क्योंकि भारत-नेपाल संधि में नेपाल से होने वाले आयातों पर किसी प्रकार के सीमाशुल्क (या विशेषतः पाटनरोधी शुल्क) को लगाए जाने से खुला छूट का प्रावधान नहीं है। नेपाल से भारत को जिक्र आक्साइड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के एक अन्य मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 6 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं० 7/1/2001-डीजीएडी के द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने के बारे में केन्द्रीय सरकार का सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने अब इस सिफारिश को लागू कर दिया है और 12 सितम्बर, 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 93/2001 जारी करते हुए नेपाल से जिक्र आक्साइड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसलिए, प्राधिकारी इस आधार पर निर्यातक के तर्क को स्वीकार्य नहीं मानते हैं।

(ठ) नेपाल के अन्य निर्यातक/उत्पादक34. सामान्य मूल्य

चूंकि किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने सूचना नहीं दी है इसलिए प्राधिकारी ने मैसर्स रिलायंस स्पिनिंग मिल्स लि० के संबंध में यथा-निर्धारित सामान्य मूल्य को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है। संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य ...रुपए/किग्रा० या ... अमरीकी डालर/किग्रा. माना जाता है।

35. निर्यात कीमत

प्राधिकारी ने उस प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर अन्य निर्यातक/उत्पादक के संबंध में निर्यात कीमत को निकालने हेतु न्यूनतम निर्यात कीमत को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है। स्वदेशी भाड़े (जोगबानी तक), बीमा उद्गम प्रमाण-पत्र, निर्यात शुल्क, हैंडलिंग एवं फारवर्डिंग के लिए ... रुपए/किग्रा., ... अमरीकी डालर/किग्रा. तक के समायोजन करने के पश्चात कारखानागत निर्यात कीमत ... रुपए किग्रा. या ... अमरीकी डालर/किग्रा. बैठती है।

36. पाटन मार्जिन

अन्य निर्यातको/उत्पादकों, जिन्होंने सूचना नहीं दी है, के संबंध में पाटन मार्जिन 61.76% बैठता है।

ड भारतीय उद्योग का हित व अन्य मुद्दे

37. सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य उस पाटन को कम करना है जो घरेलू उद्योग का क्षति पहुँचा रहा है और नये सिरे से भारतीय बाजार में एक खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को कायम करना है जो देश के आम हित में है।

38. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से एक्रीलिक यार्न का उपयोग करते हुए उत्पादित वस्तुओं के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी कार्रवाई द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा तथा संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता के लिए एक व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय से नेपाल से होने वाले आयातों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी और इसलिए इससे उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे ज्यादा स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।

(ढ) पहुँच मूल्य

39. अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तु के लिए पहुँच मूल्य का निर्धारण भारत सीआईएफ निर्यात कीमत, सीमाशुल्क का लागू स्तर (धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) और 1% उत्तराई प्रभारों का जोड़ने के पश्चात् की गई है।

(ण) निष्कर्ष

40 प्राधिकारी उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि

- (i) नेपाल से एक्रीलिक यार्न का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।
- (ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है तथा उसे आगे और क्षति का खतरा है।
- (iii) यह क्षति नेपाल से पाटित आयातों के कारण हुई है।

41. प्राधिकारी अंतिम निर्धारण होने तक नेपाल से एक्रीलिक यार्न के सभी आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता पर विचार करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर की जा सके। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश पर विचार किया गया।

42. तदनुसार, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि सीमाशुल्क शीर्ष 5402 और 5509 के अन्तर्गत आने वाले नेपाल के मूल की और या वहां से निर्यातित एक्रीलिक यार्न के सभी आयातों पर अंतिम निर्धारण होने तक केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे यथा-निर्धारित अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

देश	पाटनरोधी शुल्क (अमरीकी डालर/किग्रा.)
नेपाल	
निर्यातक/उत्पादक : मैसर्स रिलायंस स्पनिंग मिल्स लि०	०.६१
नेपाल के अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	०.८४

त. आगे की प्रक्रिया

43. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी

(क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों से इन निष्कर्षों के बारे में टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम निष्कर्षों में विचार किया जाएगा

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों, याचिकाकर्ताओं तथा अन्य ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 40 दिनों के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इन निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है।

(ग) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पार्टियों को मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया जाना है। मौखिक सुनवाई के लिए तिथि तथा समय के बारे में सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को बाद में सूचित किया जाएगा।

(घ) प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक और आगे जांच करेंगे।

(ङ) अन्तिम निष्कर्षों की घोषणा करने से पहले प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 25th September, 2001
PRELIMINARY FINDINGS

Subject: Anti-dumping investigation concerning Imports of Acrylic Yarn originating in or exported from Nepal - preliminary findings.

No. 29/1/2001-DGAD.— The Government of India having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed:-

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s. Punjab Fibres Ltd., Nawan Shahar, Punjab; M/s. Vardhman Spinning & General Mills Ltd., Ludhiana; M/s. Sportking India Ltd., Ludhiana; M/s. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd., Ludhiana on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Acrylic Yarn (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from Nepal (hereinafter referred to as subject country) ;
- (ii) The Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of dumping application made by the petitioners before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*;
- (iii) The Authority issued a Public Notice dated 3rd July, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Acrylic Yarn originating in or exported from Nepal

classified under heading 5402.39, 5402.69 and under sub-heads of heading 5509 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975;

- (iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, chambers of commerce and to the complainants and gave them an opportunity to make their views known in writing.
- (v) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters and Embassy of subject country in India.
- (vi) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following exporters:
 - 1. M/s. Reliance Spinning Mills Ltd., Distt. Sunsori, Nepal.
 - 2. M/s. Reliance Spinning Mills Ltd., Kathmandu, Nepal.
- (vii) The Embassy of Nepal in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;
- (viii) The exporter from Nepal sought extension of time for furnishing of reply and the Designated Authority, having regard to Rule 6(4) supra, allowed extension of one week for submission of response by the exporter, in view of sufficient cause having been shown by the exporter.
- (ix) The questionnaire was sent to the following importers/users of Acrylic Yarn:
 - 1. M/s. Kaur Sain Traders, Ludhiana.
 - 2. M/s. Goyal Agencies, Delhi.

The above importers sought extension of time for furnishing of reply as given in the case of the exporters. The Authority considered the request and allowed similar extension of time of one week for submission of reply by the importers as allowed in the case of exporters.

- (x) Among the users/importers, response to the questionnaire was filed by M/s. Kaur Sain Traders, Ludhiana and M/s. Goyal Agencies, Delhi. Among the exporters, M/s. Reliance Spinning Mills Ltd., Distt. Sunsori, Nepal having their corporate/head office at Kathmandu, Nepal has filed response to the questionnaire.
- (xi) Additional information regarding injury was sought from the petitioners, which was also furnished;

- (xii) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;
- (xiii) ***** in this notification represents information furnished by the interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;
- (xiv) The Authority sought and verified information given by the domestic industry and to this end investigations were carried out at the premises of the petitioners at Ludhiana in Punjab;
- (xv) The Authority also conducted cost investigation and worked out optimum cost of production and cost to make and sell subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles;
- (xvi) The investigation covered the period from 1st April, 2000 to 31st March, 2001.
- (xvii) Copies of initiation notice were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

B. PETITIONER'S VIEWS

- 3. The petitioners have made the following major points in their submissions:
 - (i) The petitioners' represent the domestic industry and Acrylic Yarn being produced by the petitioners is a like product to the Acrylic Yarn being imported from subject country.
 - (ii) Exporters from Nepal are dumping subject goods in India and the petitioners have, therefore, approached the Designated Authority for considering levy of anti dumping duty.
 - (iii) Regarding the normal value, petitioners made efforts to get information on the domestic prices of subject goods in subject country. However, they could not get a reasonable and authentic evidence of the local prices charged by the manufacturers in the Nepal or for their exports to other countries. Therefore they constructed the normal value in Nepal on the basis of the details of cost of production for basic raw material and prices of utilities, manufacturing, administrative and selling expenses, etc., on the basis of the industry norms;

- (iv) The export price has been claimed on the basis of the data compiled by the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta. Adjustments have been claimed on account of freight, insurance, commission, loading of material, to arrive at net export price at ex-factory level.
- (v) There has been significant increase in the imports of Acrylic Yarn from Nepal in the last two-three years. The imports increased from 0.16 million kgs in 1996 to 18 million kgs in 2001. The imports from Nepal have increased in actual terms;
- (vi) The capacity for Acrylic Yarn manufacture being created in Nepal are primarily to target Indian market only;
- (vii) The market share of imports from Nepal in India has increased from 8.36% in 1998-99 to 27.37% in 2000-01;
- (viii) The imports of subject goods are being made from Nepal at dumped prices since the normal value determined on constructed cost of production is significantly higher than the export price. The dumped imports are causing serious injury to the domestic industry;
- (ix) Due to the dumping of subject goods the domestic industry production has either stagnated or declined. Whereas, the share of imports from Nepal has increased in the overall demand of Acrylic Yarn;
- (x) The domestic industry has suffered injury due to price under-cutting as the industry has been forced to sell its product at severe losses. The cost of production of the domestic industry increased significantly. However, sales realization of the petitioners could not be increased to a level of reasonable profitability. The landed value of the imported material from Nepal is significantly below the selling price of the domestic industry causing severe price under-cutting in the Indian market.
- (xi) The domestic industry has suffered injury due to dumped imports causing price suppression/depression. The landed value of imports of subject goods from Nepal is significantly below the cost of production of the domestic industry causing price suppression, depression in the Indian market.
- (xii) The domestic industry has suffered significant losses due to selling of the subject goods at selling price lower than the cost of production resulting in losses continuously;

C. EXPORTERS' VIEWS

4. The exporters have expressed following views in their response:

- (i) Under Indo-Nepal Treaty import of goods are to be allowed free of customs duty in India. Anti-dumping duty imposed under Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 has been held to be a Customs duty by the Hon'ble Supreme Court in the case of *Hyderabad Industries Ltd. v Union of India*. Therefore, no duty can be imposed on exports from Nepal;
- (ii) The petitioners do not have the required standing as they do not represent even 25% of domestic Indian manufacturers of Acrylic Yarn. In the absence of standing, the initiation is bad in law and investigations should be terminated.
- (iii) The net availability of Acrylic Fibre during the investigation period was 1,15,299.6 MT taking yarn realization from Fibre as 98%, the Acrylic Yarn production in India would therefore be 112,993.6 MT. As against this, the production of the petitioners is only 19,883.2 MT and the share of the petitioners is thus only 17.59% and not 54% as claimed. The figure of 36.55 million kg production of Acrylic Yarn given in the petition is grossly understated. The Ludhiana Spinners Association is an interested party in the proceedings and therefore information may be collected from authentic sources;
- (iv) There are factual errors in the petition as under:-
 - a) Their exports of Acrylic Yarn to India has been under the heading 55.09 and the petitioners statement that exports are taking place under different sub-heads of Chapter 54 and 55 is incorrect. The statement that the exporters of Nepal are misdeclaring the goods is totally false. In the petition no information has been given regarding the imports of Acrylic Yarn. The data provided in respect of other materials therefore does not indicate the volume or value of the exports of Acrylic Yarn from Nepal.
 - b) The statement that no other type of yarn is produced in Nepal is incorrect as there are number of manufacturers of polyester spun yarn/polyester texturised yarn in Nepal, who, also export to India.
 - c) It is not correct to say that no customs duty are chargeable on the imports from Nepal, as additional duty (CVD) is collected on the imports from Nepal.
 - d) The spindle capacity of 21 million kgs in Nepal is highly exaggerated. It is incorrect to say that no viable substitute is there for Acrylic Yarn. Acrylic Yarn has been substituted mainly by

Polypropylene Yarn and other types of yarn. Since the imposition of anti-dumping duty on Acrylic Fibre from Thailand, Korea and USA the cost of raw material in India has become very high. The Indian industry is deprived of a cheap source of raw material and as a consequence has become uncompetitive in the international market.

- e) Due to emergence of viable substitutes there has been a contraction in the overall demand for Acrylic Yarn. It is incorrect to say that the production of petitioners has declined since the production has actually increased during the period of investigation.
- f) It is incorrect to say that the cost of production in Nepal cannot be lower than the cost of production in India. The exporter in Nepal has access to cheap Acrylic Fibre available from Thailand. Therefore, the cost of manufacture in Nepal is at least Rs.15 to Rs.20 less than in India. The estimation of normal value by the petitioners is therefore wrong.
- g) It is incorrect to state that the export price should be reduced by the amount of freight from the factory in Nepal to the destination of a customer in India. The freight amount to be deducted is only the freight up to the Indian border at Jogbani. No commission is paid to any agent and the goods are directly sold to traders in India.
- h) The calculation of the anti-dumping margin in the petition is absolutely incorrect as both the normal value and export price calculations are erroneous.
- i) The claim that petitioners have suffered injury is incorrect as their share in production has doubled during the period of investigation.
- j) It is incorrect to say that the cost of production of the domestic industry has increased significantly as there has been no serious increase in the prices of raw material internationally during the period of investigation. The increase in the cost of the domestic industry is on account of imposition of duty and the consequent competitive advantage available to the exporter cannot be termed as dumping. This is a legitimate advantage available to them and therefore there is no basis for alleged dumping.
- k) In the calculation of fair selling price the petitioners have shown 10% profit margin which is very high as compared to the industry level. The cost of production of the domestic industry is high on account of duty on fibre and also the petitioners operate inefficiently and are burdened with high financial cost. It is not correct to say that landed value of subject goods is below the cost of production of the petitioners.
- l) There is a total absence of causal link between the exports from Nepal and injury, if any, to domestic industry. The injury, if any, is as a result of contraction in overall demand and the anti-dumping duty imposed on Acrylic Fibre.

- (v) There is total absence of dumping in this case. As per the exporters, they do not have the resources to incur losses in exports to their only market which is India. They have not made any sales of Acrylic grey yarn in Nepal. Therefore, the domestic prices of grey yarn are not available.
- (vi) There is a total absence of injury to the petitioner as it is evident that the production of the petitioners has increased during the period of investigation. There has been no price under-cutting in this case. The petitioners have shown very high cost of production which is inflated on account of high unit price of fibre, high interest cost, less number of man-hours per year and low productivity. Injury, if any, is not on account of the exports from Nepal.
- (vii) There is no causal link between the exports and the injury if any to domestic industry. The Designated Authority is requested to examine any known factors other than the dumped imports which might be injuring the domestic industry.
- (viii) The main cause for the injury to the Indian industry is the impact of anti-dumping duty on Acrylic Fibre. These duties have effectively deprived the Indian manufacturers access to cheap Acrylic Fibre. This has reduced the competitiveness of the Indian manufacturers.

D. EXAMINATION AND FINDINGS BY AUTHORITY

5. The submissions made and the information provided by the exporters, importers and the domestic industry have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter. The Authority observed that the exporter has given information in respect of the questionnaire selectively. In the initial response the exporter chose not to give information on domestic sales in Appendix-1. Similarly, information about domestic market sales for current year and preceding two years as required in Appendix-3 was not given. The information about export sales data for preceding two years was also not given for April-March period for proper comparison and instead data was given for 17th July to 16th July period. Sales price structure for domestic sales (Appendix-5), factory cost and profit of domestic sales (Appendix-9) were not furnished. On being asked to clarify about information on domestic sales, the exporter gave information about domestic sales transactions on Appendix-1, however, other information as above has not been given. Therefore, the exporter gave selective information and did not make a complete response. The shortcomings in the response have also been dealt with in the findings wherever considered appropriate.

6. The cases of new exporters or those stated to be willing to give price undertaking shall be considered, on request, by the Authority in accordance with the Rules supra.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. The product under consideration is Acrylic Yarn. Acrylic Yarn is made of acrylic fibre and spun in mainly 3-4 counts. It can be made either from 100% acrylic fibre or in combination of 90% acrylic fibre blended with 10% polyester or viscose or 85% acrylic fibre blended with 15% polyester or viscose. Acrylic yarn is used for production of knitwears, hosiery, shawls etc. Acrylic Yarn imports are covered under various sub-headings of Customs Tariff Classification Major Head 5402 like 5402.39 and 5402.69 and also under sub-heads of Major Head 5509. These Custom classifications are however, indicative only and are in no way binding on the scope of the investigation.

8. The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from Nepal. The exporters had not raised any point on this issue in their initial response and had given selective information. However, when they were asked to clarify on the issue of domestic sales, they raised the point that grey and dyed Acrylic Yarn should be considered as separate products as they are not technically and commercially interchangeable. While doing so the exporters gave details of domestic sales of Acrylic dyed yarn as required under Appendix-1 of questionnaire. The Authority has examined the views expressed by the exporters as regards like article. The product involved in the present investigation is Acrylic Yarn as mentioned in the para 2 of the initiation notification dated 3.7.2001. Acrylic Dyed Yarn had not been excluded from the purview of the present investigation. The information regarding exports made by the exporter during the period of investigation also includes exports of Acrylic Dyed Yarn. The Authority considers that Acrylic Grey Yarn and Acrylic Dyed Yarn are technically same product except that grey yarn when dyed becomes dyed yarn. These are mutually substitutable. The Authority did not agree to the contention of the exporter to exclude Acrylic Dyed Yarn from the present investigation and therefore for the purpose of investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' of the product involved, i.e. Acrylic Yarn imported from the subject country within the meaning of the Rules supra.

F. DOMESTIC INDUSTRY

9. There are several producers of the subject goods in India, however, the petition has been filed by M/s. Punjab Fibres Ltd., Nawanshahr, Punjab; M/s. Vardhman Spinning & General Mills Ltd., Ludhiana; M/s. Spinning India Ltd.,

Ludhiana; M/s. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd., Ludhiana. As per the petition the estimated production of Acrylic Yarn during April 2000 to March, 2001 (POI) was 36.65 million kg and the production of the four petitioners during this period was 19.884 million kg which is 54.4% of the production. However, the production figures of Acrylic Yarn were verified from the office of the Textile Commissioner, Mumbai who have informed that the total production of Acrylic spun yarn during the period of investigation was 64.94 million kgs and the share of the four petitioners was 22.59 million kgs which comes to 34.79%. The exporter has raised the point regarding standing of the petitioner. However, they have derived the Acrylic Yarn production figure from Acrylic Fibre. There is a possibility of use of Acrylic Fibre in manufacture of different blends of yarn, besides, any other usage. There are also some exports of Acrylic Fibre from India. As the exporter has not furnished any authentic data regarding the production of Acrylic Yarn during POI, the authority considers it appropriate to rely upon the information received from the office of the Textile Commissioner, Mumbai and therefore, the petitioners, who account for more than 25% of the total production of the like article, are treated to represent the domestic industry in terms of Rule 5 supra. During the course of the investigation the following domestic producers have also supported the petition for anti-dumping investigation into the dumping of Acrylic Yarn from Nepal:

Name of the domestic producer	Production In 2000-2001 (MT)
M/s. Vardhman Polytex, Ludhiana.	2333
M/s. Garg Acrylics Ltd., Ludhiana.	983.5
M/s. Adinath Textiles Ltd., Ludhiana	895
M/s. Mahavir Spinning Mills Ltd., Ludhiana	3240
M/s. Arisudana Industries Ltd., Ludhiana	3820
M/s. Deepak Spinners Ltd., Chandigarh	2296
M/s. Supreme Woolen Mills Ltd., Ludhiana	4997

G. DUMPING & EXAMINATION OF CLAIMS MADE ON NORMAL VALUE & EXPORT PRICES

Normal Value

10. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:
 - (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section(6); or

- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

11. The Authority sent questionnaires to the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). However, response was received only from M/s. Reliance Spinning Mills Ltd., Distt. Sunsori, Nepal having their corporate/head office at Kathmandu Nepal. According to exporters they have not made any sales of Acrylic Grey Yarn in Nepal. Therefore, the domestic prices of grey yarn are not available. As regards, dyed Acrylic Yarn, they have exported a very small quantity in the count of 1/40. Acrylic Yarn of this count has however not been sold in the domestic market in Nepal. Therefore, according to the exporter, the normal value cannot be determined based on domestic sale prices in Nepal. Though the exporter had not furnished information relating to the domestic sales, the information furnished did reflect that there were domestic sales of the product involved in the investigation, i.e. Acrylic Yarn. The exporter was asked to clarify on this inconsistency. The exporter responded stating that grey and dyed Acrylic Yarn should be considered as separate product as they are not technically and commercially interchangeable. While furnishing the clarification the exporter submitted information relating to domestic sales of Acrylic Dyed Yarn. Complete information on the prescribed format has not been furnished regarding sale price structure for domestic sales. The factory cost and profit of domestic sales as per Appendix 9 has also not been furnished. As per information furnished by the exporters the quantum of domestic sales of Acrylic Dyed Yarn is *** MT. This is 2.3% of the exports made by the exporter of the product involved during the Period of Investigation. According to Section 9A(1)(c)(ii), when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation **or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison**, the normal value shall be either

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

12. Article 2.2 of the WTO Agreement on Anti-Dumping is relevant here. An explanation to the term 'low volume of sales in the domestic market' has been provided as a footnote stating that "sales of the like product destined for consumption in the domestic market of the exporting country shall normally be considered a sufficient quantity for the determination of the normal value if such sales constitute 5% or more of the sales of the product under consideration to the importing member, provided that a lower ratio should be acceptable where the evidence demonstrates that domestic sales at such lower ratio are nonetheless of sufficient magnitude to provide for a proper comparison". The domestic sales of Acrylic Dyed Yarn constitute only 2.3% of the exports made by the exporter in this case. Therefore, these domestic sales are not treated as sufficient to provide for a proper comparison. As per the information furnished there are no exports made by the exporter to any other country. Therefore, section 9A(1)(c)(ii)(a) for determination of normal value on the basis of comparable representative price of the product when exported to a third country, is also not applicable in this case.

13. Therefore, for determination of normal value section 9A(1)(c)(ii)(b) becomes applicable, i.e. the normal value is to be determined on the basis of the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6). In accordance to Rule 10 and Principle 1 of the Annexure -1 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the element of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sales of the article under consideration. The period of investigation in this case is from 1st April, 2000 to 31st March, 2001. The exporter had sought extension of time for submission of response on various grounds and one of the grounds was that in Nepal the financial year is as per Hindu calendar starting from 17th July, which is different from the POI and therefore they had to prepare the information keeping in view the investigation period. The Authority had allowed one-week extension for submission of reply. Even after this extension the exporter has not furnished

complete information for the period of investigation. The financial information furnished by the exporter is incomplete as the balance sheet and profit and loss account for the period 16th July 2000 to 13th April, 2001 has been furnished which does not serve the requirement of proper verification of costing information for the product under consideration for the investigation period. The information on the factory cost and profit of domestic sales on the prescribed format has not been furnished. Sales price structure for domestic sales has also not been furnished. Therefore, the Authority disregards the costing information furnished. The claims made by the exporter in relation to various aspects of cost determination like cost of raw material, accounting of interest and financial expenses, allocation of costs per frame, dyeing and chemicals cost, etc. are subject to verification on receipt of complete information.

14. For the Preliminary determination the Authority therefore, determines the normal value on the basis of best available information. While doing so the Authority has considered the information furnished by the exporter as regards the cost of the raw material, i.e. Acrylic Fibre. The exporter had produced evidence of CIF Calcutta Price of the raw material Acrylic Fibre. However, the Authority has added Rs.*** towards freight and border clearance charges for the raw material till it reaches the factory of the exporter. The cost of production, selling, general and administrative expenses have been determined on the basis of best available information. According to the available information the normal value determined by the Authority for the product under consideration is Rs.*** /Kg. US \$*** /Kg. pending final determination.

Export price

15. M/s. Reliance Spinning Mills Ltd., Distt. Sunsori, Nepal has furnished information regarding their exports to India during the period of investigation. There are five consignments of exports of Acrylic Dyed Yarn in the statement of exports furnished and the remaining consignments relate to export of Acrylic 100% Grey Yarn. On the basis of the available information regarding dyeing cost, necessary adjustments have been made in the FOB value of exports. After making these adjustments the weighted average FOB export price of Acrylic Yarn to India works out to Rs.*** US \$*** per Kg. The exporter has shown adjustments of Rs.*** US \$*** from the assessable value of export price on account of inland freight (up to Jogbani), insurance, certificate of origin, export duty, handling and forwarding. The exporter has claimed that freight from the Nepal border to the destination in Ludhiana is borne by the importers and the export invoices do not include this freight amount. The Authority finds that the export invoices do not show any terms of delivery i.e., FOB or CIF. As per the Bills of Entry furnished, assessable value is arrived at by adding amounts on account of freight(factory to Nepal border), insurance, certificate of origin charges, loading charges and Nepalese customs charges. As these charges are incurred up to the point of goods reaching the Nepal border and as the importer pays for the amount as per the export invoice only, it is considered appropriate to

make adjustments on these accounts from the invoice value. Therefore, an adjustment of RS.*** US\$*** /Kg. has been made on these accounts from the weighted average export price. After making these adjustments the net export price has been worked out as Rs.***US \$*** per Kg. for the period of investigation.

Dumping margin

16. The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin as laid down in the Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rules are elaborated in Annexure I to the Rules. For the purpose of the fair comparison between the normal value and export price, the Authority has made calculations and comparisons at the same level of trade. Normal Value based on the constructed cost of production at ex-factory level has been compared with the weighted average export price. While doing so due allowance has been made for dyeing costs.

17. The normal value based on the constructed cost of production works out to Rs.*** per Kg. US\$ *** /Kg. The net export price at ex-factory level worked out as above after making adjustments comes to Rs.*** /Kg Us\$*** /Kg. The dumping margin in respect of the exports of the subject goods by M/s Reliance Spinning Mills Ltd., Nepal comes to 45.9 % of the export price.

H. INJURY

18. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

“Determination of Injury:

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

(2) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.”

The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

- i. A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
- ii. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

19. The Authority has examined the information regarding volume of imports during the period of investigation and the two preceding years, i.e. 1998-99 and 1999-2000. The Authority found that there is lot of variance in the volume of imports relating to these years as shown in various sources, viz., Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCIS), the petitioners, the exporters, the importers and the Indian Embassy in Nepal. The DGCIS, in response to the initiation notification, sent data showing imports of Acrylic Yarn from Nepal under ITC Classification 5402.39/69, 5590.61/62/69 as 3436 MTs in 1999-2000 and 1165 MTs during (April 2000 – February 2001). Considering the wide variance in the import volumes of different sources, the Authority considers it appropriate to compare the trend of increasing imports on the basis of the information furnished by the exporters and importers. The information relating to preceding two years exports furnished by the exporter could not be useful as the exporters gave this information with reference to the Nepalese financial year, i.e. from 17th July to 16th July, whereas, the POI was 1st April, 2000 to 31st March, 2001. This did not allow a proper comparison. Based on the information furnished by the two importers, the imports grew from 4790 MT in 1998-99 to 7481 MT in 1999-2000 registering an increase of 56% and from 7481 MT in 1999-2000 to 9572 MT in 2000-01 an increase of 27%. The Authority finds that the volume of imports from Nepal have increased significantly during the last three years. The increase in the imports of the product involved during the period of investigation has been in absolute terms. There has also been a significant increase in imports in relation to the demand of the product in India from 6.53% in 1998-99 to 12.8% in 2000-2001.

20. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by

the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority finds that dumped imports from Nepal and more particularly from the exporter who has responded to the questionnaire, have increased significantly. During the period of investigation the imports grew by 27% over the previous year. Their share in the Indian demand for the product also grew from 6.53% in 1998-99 to 12.8% in 2000-01 which poses a serious threat of injury to the domestic industry.

Significant Price Under cutting

21. The price under-cutting of imports have caused a significant depressing effect on the price of the domestic industry. The domestic industry has not been able to realize a fair selling price. During the period of investigation the average Net sales realization of the domestic industry for the product involved has been Rs.***/Kg. whereas the average landed value of imported product has been Rs.***/Kg. This clearly signifies price under-cutting.

22. The evidence of price under cutting demonstrates that the domestic industry has suffered material injury. The industry has not been able to realise a fair selling price on its production of the subject goods so as to recover its costs as well as to earn a reasonable profit.

Threat of Injury

23. Under Rule 11 *supra*, Annexure II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "*.....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.....*". Further to above, regarding threat of injury, para (vii) of Annexure II of Rules *supra*, reads as under:-

" (vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, *inter alia*, such factors as:

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into

account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

(d) inventories of the article being investigated.”

24. The continuous dumped imports in large quantities has led to price suppression and the domestic industry has not been able to raise its price to the extent required to recover its cost and earn a reasonable profit. The volume of dumped imports has been significant during the period of investigation and the preceding year. There is every likelihood that imports may keep coming at dumped price in larger quantities causing serious threat of injury to the domestic industry. On the basis of the evidence available before it, the Authority therefore concludes that there is a serious threat of injury being caused to the domestic industry on account of dumped imports of subject goods from subject country.

I. CAUSAL LINK

25. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry the principle (iv) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules states:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic Industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

Views of the Exporter

26. It is the argument of the exporter that the cost of production as indicated by the petitioners is highly inflated on account of the high unit price of the fibre, high interest cost, less number of man-hours per year and low productivity. Injury, if any is not on account of the exports from Nepal. Further the fair selling price calculation as given on the petition is inaccurate and includes a number of hidden costs. The fair selling price should be determined after removing the impact of anti-dumping duty on fibre and the low efficiency of the petitioners. According to the exporters there is no dumping or injury and there is no causal link between the exports and the injury if any to domestic industry. The main cause for the injury to the domestic industry is the impact of anti-dumping duty

on acrylic fibre. These duties have effectively deprived the Indian manufacturers of access to cheap acrylic fibre.

Views of the Petitioners

27. The petitioners have stated that cost of production in Nepal could not be different than the cost of production in India, subject to the difference in raw material costs due to the custom duties payable in India. As per own admission of the exporters producers in Nepal have cost advantage of at least Rs.15-20 per KG. As per the petitioners even by giving a benefit of RS. 17.50 (average of the claim of exporter) the exports by the Nepalese producers are at a price much lower than this difference of Rs. 17.50/ Kg. The petitioners argument is that the exporters in Nepal did not recover their cost of production and that there is suppression of vital information filed by the exporters.

Examination and Findings of the Authority

28. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority considered such further indices having a bearing on the state of industry as production, sales, market share, profitability, net sales realisation etc. All the economic parameters affecting the domestic industry mentioned above have been examined. The production of the four petitioners has been 20309 MTs in 1998-99, 22300 MTs in 1999-2000 and 22594 MTs during POI (April – March, 2001). There has been a slight increase in the total production. However, their share in the market has come down from 32.7 % in 1999-2000 to 30% in period of investigation(POI) due to increase in imports in absolute terms, whereas, the share of the imports from subject country increased from 6.5% in 1998-99 to 12.8% during the period of investigation. There was an increase in imports from subject country in absolute terms by 27% during POI. The cost of production of the domestic industry has gone up from Rs.***/ kg. to Rs.***/kg. during POI. The net sales realization has been Rs.***/Kg. during 1999-2000 and Rs.***/Kg. during POI. The net sales realization is found to be lower than the cost of production signifying suffering of losses on account of production and sale of the product involved. There is an evidence of significant price under-cutting as the landed value of the product involved is less than the net sales realization. The domestic industry has also suffered due to price suppression as the landed value of the imported product is significantly below the cost of production of the domestic industry causing price suppression and thereby preventing the domestic industry to raise its price to a level to earn reasonable profits.

29. The Authority finds that the production of the domestic industry has stagnated in the face of significant increase in the imports from the subject country. As the domestic industry was not able to realize a fair selling price to recover its cost of production and a reasonable profit the industry was prevented

from augmenting its production. A slight growth in the volume of production of the domestic industry does not signify that there is an absence of injury. Rather the industry has been forced to produce below its optimum capacity. The average net sales realization of the industry are less than the cost of production of the product thereby causing severe injury to the industry. Due to the dumped imports the industry has been prevented from increasing its selling price to a level to recover the cost of production and to give a fair return on the investment. The injury on account of the non-realisation of a fair selling price has been the most severe affecting the profitability of the domestic industry.

30. In determining whether injury to the domestic industry was caused by the dumped import, the Authority has taken into account the factor that it is the increased dumped imports of subject goods at dumped prices in Indian market which has forced the domestic industry to reduce its prices to the levels not sufficient to recover the non injurious price. Therefore, the causal link between the dumped imports of subject goods from subject country and threat of injury being faced by the domestic industry is clear. The Authority therefore concludes that there is a causal link between the dumping of subject goods from the subject country and threat of injury being caused to the domestic industry during the period of investigation.

J. EXAMINATION OF OTHER FACTORS CAUSING INJURY

31. It has been argued by the exporters that the main cause for the injury to the domestic industry is the impact of anti-dumping duty on acrylic fibre. These duties have effectively deprived the Indian manufacturers of access to cheap acrylic fibre. The exporter has also attributed the injury to the domestic industry due to a contraction in overall demand for Acrylic Yarn.

32. The Authority has examined these arguments. While determining the Normal value the Authority has taken into account the fact that import of Acrylic Fibre in Nepal do not attract anti-dumping duty, whereas in India, imports of Acrylic Fibre from specified countries and exporters attract anti-dumping duty. Even while doing so the Authority has found dumping in import of subject product from the subject country. As regards the argument of the exporters that the injury to the domestic industry is due to contraction in overall demand of Acrylic yarn, the authority has found, pending final determination, that demand of Acrylic yarn in India has increased during the period of investigation. However, the share of the domestic industry reduced whereas, the share of the exporter grew from 6.5% in 1998-99 to 12.82% in the POI.

K. INDO-NEPAL TREATY

33. As per the exporter anti-dumping duty cannot be imposed on imports from Nepal as India and Nepal have entered into an agreement of co-operation in matters of trade and transit. As per clause 5 of the Treaty, Indian Government has to provide access to the Indian market free of customs duty for articles manufactured in Nepal. According to the exporter, anti-dumping duty levied under Section 9(A) of the Customs Tariff Act, 1975, is a duty and therefore cannot be levied under the Indo-Nepal Treaty. As per the Indo-Nepal Treaty document of 1996, the Article V states that "The Government of India will provide access to the Indian market free of customs duties and the quantitative restrictions for all articles manufactured in Nepal." The certificate of origin annexed to the said Article V makes the issue clear as the title of the certificate of origin states "For exports free of Basic and Auxiliary duties under the treaty of trade between His Majesty's Government of Nepal and Government of India". Therefore, the treaty refers to the exemption from levy of Basic and Auxiliary Duties and not all types of customs duties. By the own admission of the exporter, Additional custom duty (commonly known as CVD) is charged under Section 3 of the Customs Tariff Act on the imports from Nepal. The exporter has cited the case of Hyderabad Industries Ltd. v. Union of India wherein the Hon'ble Supreme Court has made observations regarding the different types of customs duty under the different Acts or Rules. Among the various kinds of duties mentioned in the said orders of the Hon'ble court, Additional custom duty chargeable under Section 3(3) of the Customs tariff Act is also included. In case the argument of the exporter is that no custom duty is chargeable on the imports from Nepal, then by their own admission Additional Custom duty under Section 3 of the Custom Act is charged on the imports from Nepal. Therefore, even if assuming that Anti dumping duty is a kind of custom duty, the same is chargeable on the imports from Nepal as the Indo-Nepal treaty does not give a blanket immunity from imposition of any kind of custom duty (or more specifically anti-dumping duty) on imports from Nepal. In another case relating to anti-dumping investigations into imports of Zinc Oxide from Nepal into India, the Designated Authority had recommended imposition of anti-dumping duties to the central government vide Notification No. 7/1/2001-DGAD dated 6th August 2001. Ministry of Finance has since implemented the recommendation by issuing Customs notification 93/2001 dated 12th September 2001 imposing anti dumping duty on imports of Zinc Oxide from Nepal. Therefore, the Authority does not find the contention of the exporter acceptable on this account.

L. OTHER EXPORTERS/PRODUCERS OF NEPAL

34. Normal Value

As no other exporter/producer has provided information, the Authority proposes to adopt the Normal Value as determined in respect of M/s Reliance

Spinning Mills Ltd. The Normal value for the subject goods is considered as Rs.*** /Kg/ or US\$*** /Kg.

35. Export Price

The Authority proposes to adopt the lowest export price from the information submitted to it for arriving at the export price in respect of other exporters/producers. After making the adjustments on account of inland freight (up to Jogbani), insurance, certificate of origin, export duty, handling and forwarding to an extent of Rs.*** /Kg. US\$*** /KG. the ex-factory export price comes to Rs.*** /Kg. or US\$*** /kg.

36. Dumping Margin

The dumping margin in respect of the other exporters/ producers who have not given information comes to 61.76%.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

37. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

38. The Authority recognises that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using Acrylic yarn and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from Nepal in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

N. LANDED VALUE

39. The Landed Value has been determined for the subject goods after adding on the weighted CIF export price, the applicable level of custom duty (except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A) and one percent towards landing charges for the purposes of preliminary determination pending final findings.

O. CONCLUSIONS

40. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) Acrylic yarn has been exported to India from Nepal below its normal value;
- (ii) the Indian industry has suffered material injury and is being threatened with further injury;
- (iii) the injury has been caused by the dumped imports from Nepal.

41. The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of Acrylic Yarn from Nepal in order to remove the injury to the domestic industry. It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping so as to remove the injury to the domestic industry.

42. Accordingly, the Authority recommends that provisional anti dumping duties as set out below be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of Acrylic Yarn falling under Customs Heading 5402 and 5509 originating in and/or exported from Nepal pending final determination. The anti dumping duties shall be as follows:-

Country -	Anti dumping duty (US\$ per KG.)
Nepal Exporter/Producer : M/s Reliance Spinning Mills Ltd.	0.69
All other Exporters/Producers of Nepal	0.84

P. FURTHER PROCEDURE

43. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:-

- (a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings;
- (b) Exporters, producers, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of despatch of the letter. Any other interested party

may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;

- (c) The authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions, which have to be rendered thereafter in writing. The date and time for the oral hearing shall be communicated to all known interested parties subsequently;
- (d) The Authority would conduct further verifications to the extent deemed necessary;
- (e) The Authority would disclose essential facts before announcing the final findings.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

